The Hindu Plus Summary: 27.12.2023

मेन्स मास्टर

समावेशी विकास के लिए एक नया अर्थशास्त्र

रघुराम राजन और रोहित लांबा की पुस्तक "ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ़्यूचर" केवल विनिर्माण क्षेत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर उच्च-स्तरींय सेवाओं के निर्यात पर जोर देने का सुझाव देती है। इस लेख में योजना आयोग के पूर्व सदस्य लेखक अरुण नायर ने रघुराम राजन के दृष्टिकोण का प्रतिवाद किया हैं। यह भारत की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियों के बारे में चल रही बहुस को दर्शाता है। यह लेख पर्याप्त नौकरियाँ और आय उत्पन्न करने में पिछली रणनीतियों की विफलता का हवाला देते हुए भारत की आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करता है। यह कौशल-नौकरी-आय बेंमेल को उजागर करते हुए पारंपरिक विनिर्माण से उच्च-स्तरीय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश करता है। विकासात्मक प्रक्रिया पर जोर देते हुए, यह समावेशी विकास चालकों के रूप में स्थानीय ग्रामीण उद्यमों की वकालत करता है। समावेशिता, स्थानीय गतिविधियों को प्राथमिकता देने और भारत की अधूरी बाजार जरूरतों का दोहन करने के लिए नीतियों की पुनर्कल्पना निरंतर आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में उभरती

भारत की आर्थिक चुनौती: नौकरियाँ और समावेशी विकास वर्तमान महों:

- नौकरी और आय की अपर्याप्तता: आर्थिक विकास के बावजूद, कई भारतीयों के पास अच्छी नौकरियों और आय की कमी है। इसका प्रमाण सामाजिक अशांति से मिलता है, जिसमें किसान, अनौपचारिक श्रमिक और ठेका श्रमिक बेहतर स्थिति की मांग कर रहे हैं।
- कौशल-नौकरी-आय बेमेल: उच्च-स्तरीय कौशल में निवेश पर्याप्त अच्छी नौकरियों में परिवर्तित नहीं हुआ है। लोगों को काम करते समय संबंधित कौशल सीखने और कौशल-आय की सीढी पर चढने के अवसरों की आवश्यकता होती
- उच्च स्तरीय सेवाओं पर अत्यधिक जोर: नीतियां ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर विनिर्माण और मुल्य वर्धित सेवाओं की क्षमता की उपेक्षा करती हैं, जिससे जनता को काफी लाभ हो सकता है।

प्रस्तावित समाधानः

- समावेशी और सतत विकास की ओर बदलाव: आर्थिक विकास से रोजगार सुजन और बढ़ी हुई कमाई के माध्यम से सभी को लाभ होना चाहिए। बड़े पैमाने के उद्यमों को सीमित संसाधनों की आवश्यकता होती है जिनकी भारत में कमी है।
- ग्रामीण विनिर्माण और सेवाओं में निवेश करें: खेतों के पास छोटे, श्रम-केंद्रित व्यवसाय कृषि उपज में मूल्य जोड़ सकते हैं और स्थानीय आर्थिक गतिविधि बना सकते हैं।
- कौशल विकास में सुधार: शिक्षा और प्रशिक्षण को स्थानीय नौकरी के अवसरों के साथ जोड़ा जाना चाहिए और अनौपचारिक और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए।

- भारत में भारत के लिए और अधिक बनाएं: घरेलू जरूरतों के लिए घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करें, आयात और विदेशी निवेश पर निर्भरता कम करें।
- स्थानीय आर्थिक जाल को अपनाएं: ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों के घने नेटवर्क स्थायी विकास पैदा करते हैं और श्रमिकों के लिए स्थान संबंधी चनौतियों का समाधान करते हैं।
- सीखना और कौशल अधिग्रहण: आर्थिक सिद्धांत अक्सर नए कौशल सीखने वाले व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज कर देते हैं, जो विकास के लिए केंद्रीय है।
- सीमित राज्य क्षमता: भारत की वित्तीय सीमाओं के कारण जनता के लिए गारंटीकृत लाभ के बिना कर कटौती और प्रोत्साहन से बचने के लिए सावधानीपूर्वक खर्च करने की आवश्यकता होती है।
- बदलता वैश्विक संदर्भ: दुनिया की फैक्ट्री के रूप में चीन का युग लुप्त हो रहा है। भारत घरेलू उत्पादन के माध्यम से अपनी अधूरी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करके उत्पादकों को आकर्षित कर सकता है।

आगे बढने का रास्ता :

- भारत को पुराने आर्थिक मॉडलों से अलग होने और अपने विकास पथ की फिर से कल्पना करने की जरूरत है।
- ध्यान अच्छी नौकरियाँ पैदा करने, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाने पर होना चाहिए।
- यहां कोई छोटा रास्ता नहीं है; भारत को समावेशी आर्थिक विकास की बुनियादी बातों पर वापस लौटना होगा।

संख्याओं का नियम

संसद का हालिया शीतकालीन सत्र उथल-पुथल में समाप्त हो गया क्योंकि सत्तारूढ दल द्वारा विपक्ष के साथ बातचीत करने से इनकार करने के कारण 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिससे महत्वपूर्ण बहस में बाधा उत्पन्न हुई और व्यापक चर्चा के बिना महत्वपूर्ण कानून पारित हो सके। प्रभावशाली कानून के पारित होने के माध्यम से कार्यकारी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि ने संसदीय कार्यवाही की निष्पक्षता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में असहमति की आवाज़ों के दबदबे के बारे में चिंताएँ बढ़ा दीं।

महत्वपूर्ण मुद्दे:

• बड़े पैमाने पर विपक्ष का निलंबन: लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघनै के संबंध में विरोध प्रदर्शन के बाद 140 से अधिक विपक्षी सांसदों को दोनों सदनों (४६ राज्यसभा, १०० लोकसभा) से निलंबित कर दिया गया।









क्या हमारी निर्यात वृद्धि व्यापक है?

• विपक्ष के आरोप: विपक्ष के नेता खड़गे ने निलंबन को "पूर्व नियोजित" बताया और उचित प्रक्रिया की कमी की आलोचना की।

• एकतरफा कानून निर्माण: आपराधिक संहिता, दूरसंचार और चुनाव आयोग से संबंधित नए कानून अधिकांश विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित किए गए, जिससे बढ़ी हुई कार्यकारी शक्ति के बारे में चिंताएं बढ़ गईं।

- निष्पक्षता संबंधी चिंताएँ: लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापित दोनों को सत्र के संचालन और सरकार के प्रति कथित पूर्वाग्रह के बारे में सवालों का सामना करना पडा।
- सुरक्षा उल्लंघन पर बहस: सुरक्षा उल्लंघन पर बयान देने की विपक्ष की मांग को सरकार ने अस्वीकार कर दिया, इसे एक प्रतीकात्मक शक्ति खेल के रूप में देखा गया।
- मिमिक्री विवाद: एक विपक्षी सांसद द्वारा राज्यसभा के सभापित की कथित मिमिक्री ध्यान भटकाने वाली, देरी करने वाली और कार्यवाही को पटरी से उतारने वाली बन गई।

संसदीय सत्र की गतिशीलता:

- विपक्ष का विघटन: सत्तारूढ़ भाजपा के विपक्ष के साथ जुड़ने से इनकार के कारण संसदीय सत्र अनुत्पादक रहा।
- विपक्षी सदस्यों का निलंबन: लोकसभा कक्ष में प्रदर्शनकारियों के प्रवेश से जुड़े सुरक्षा उल्लंघन के संबंध में बयान की मांग करने पर 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया।
- कार्यकारी जवाबदेही का अभाव: सरकार ने जवाबदेही से परहेज किया, पर्याप्त बहस या विरोधी विचारों पर विचार किए बिना प्रभावशाली विधेयकों को पारित किया।

विधायी प्रभाव:

- कानूनों का एकतरफा पारित होना: आपराधिक संहिता, दूरसंचार नियमों और चुनाव आयोग की नियुक्तियों में बदलाव करने वाले कानून विपक्ष की पर्याप्त उपस्थिति की अनुपस्थिति के बीच पारित किए गए।
- कार्यकारी शक्ति में वृद्धि: विविध दृष्टिकोणों को शामिल करते हुए व्यापक संसदीय बहस के बिना पारित किए गए इन कानूनों ने कार्यकारी के अधिकार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया।

विवाद और प्रतिक्रियाएँ:

- संख्यात्मक बहुमत बनाम जवाबदेही: संख्यात्मक बहुमत को अचूकता के साथ जोड़ने के सरकार के रुख ने जवाबदेही और सार्थक बहस की मांगों को नजरअंदाज कर दिया।
- दोषारोपण का खेल: सरकार ने अपने निलंबन के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया, इस स्थिति का अध्यक्ष और सभापित ने समर्थन किया, जिससे संसदीय कार्यवाही कमजोर हुई।
- ध्यान भटकाने की रणनीति: कथित नकल की घटना और सुरक्षा उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान भटक गया, जिससे संसदीय कामकाज पटरी से उतरने की संभावना है।

समग्र प्रभाव:

• संसदीय कामकाज का पटरी से उतरना: सत्र का ध्यान ध्यान भटकाने वाला रहा और पर्याप्त बहस की कमी ने कार्यपालिका को खुली छूट देने की कोशिश की, जिससे प्रभावी संसदीय कामकाज बाधित हुआ। 2022 में भारत की वैश्विक व्यापार गतिविधियों का परीक्षण करें। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहल क्या हैं? भविष्य में भारत की वैश्विक व्यापार भागीदारी को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सुझाएँ। 38 एम 68वीं बीपीएससी मेन्स

संदर्भ

लेख में 2023 में भारत के व्यापार परिदृश्य का आकलन किया गया है, जिसमें देश के व्यापार प्रदर्शन पर वैश्विक कारकों के प्रभाव को रेखांकित किया गया है। यह माल और सेवाओं के निर्यात में विपरीत रुझानों के साथ समग्र व्यापार में गिरावट को उजागर करता है, जिसमें विकास और गिरावट वाले क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह सेवा निर्यात के महत्व, डेटा सटीकता में चुनौतियों, चल रहे मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता, आगामी डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और अमेरिका और यूरोपीय संघ के व्यापार-संबंधी दबावों पर प्रकाश डालता है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद व्यापार प्रदर्शन को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ, श्रम-गहन क्षेत्रों, सेवा विविधीकरण, एफटीए निहितार्थ और व्यापार नीति प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए, व्यापार चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के लिए रणनीतियों का सुझाव देते हुए यह लेख समाप्त होता है।

भारत का व्यापार परिदृश्य:

- जीडीपी प्रभाव: 2023 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत की जीडीपी क 43.1% है, जिसमें निर्यात और आयात एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: निर्यात सकल घरेलू उत्पाद में 20.5% का योगदान देता है, जो चुनौतियों के बावजूद भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

व्यापार सांख्यिकी और रुझान:

- 2023 व्यापार अवलोकन: 2023 में भारत का व्यापार 1,609 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.6% की मामूली गिरावट है।
- निर्यात गतिशीलता: माल निर्यात में 5.3% की गिरावट के बावजूद सेवाओं में उल्लेखनीय 10.5% वृद्धि के कारण निर्यात में मामूली 1% की वृद्धि हुई।
- वैश्विक संरेखण: भारत का व्यापार प्रदर्शन 5% की गिरावट की वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो चीन के व्यापारिक निर्यात में 5.2% की गिरावट के साथ संरेखित है।

निर्यात श्रेणियाँ:

- गिरावट वाले क्षेत्र: भारत के अधिकांश व्यापारिक निर्यात (78%) को कम लागत वाले देशों से प्रतिस्पर्धा के कारण नकारात्मक वृद्धि का सामना करना पडा।
- सफल निर्यात: स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, चावल और कुछ वस्तुओं सहित 22% निर्यात में वृद्धि देखी गई। सेवा क्षेत्र का विकास:
- सेवा निर्यात में वृद्धिः सेवा निर्यात में 10.5% की वृद्धि का अनुमान है, जो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर, आईटी सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं द्वारा संचालित है।

pragyesh.org

• वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी): वैश्विक कंपनियों द्वारा स्थापित 1,500 से अधिक जीसीसी. लगभग 1.3 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देते हैं









चुनौतियाँ:

- समग्र व्यापार में गिरावट: 2023 में भारत के व्यापार में थोडी गिरावट आने की उम्मीद है, जो वैश्विक रुझान को दर्शाता है।
- माल निर्यात में गिरावट: अधिकांश उत्पाद श्रेणियों (७८%) में नकारात्मक वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से इंजीनियरिंग और परिधान जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में।
- कम लागत वाले देशों से प्रतिस्पर्धाः बांग्लादेश और वियतनाम भारतीय निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं।
- रुपये का मूल्यहास: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6% मूल्यहास के बावजूद, यह निर्यात को बढावा देने के लिए पर्याप्त नहीं था।

अवसर:

- इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में वृद्धिः २०२३ में स्मार्टफोन निर्यात दोगुना होने की उम्मीद है, जो उच्च तकनीक विनिर्माण में भारत की क्षमता को दर्शाता है।
- सेवाओं के निर्यात का मजबूत प्रदर्शन: आईटी, सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाएं इस क्षेत्र में विकास का नेतृत्व कर रही हैं।
- वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी): भारत में 1,500 से अधिक जीसीसी स्थापित हैं. जो भारतीय पेशेवर सेवाओं की बढ़ती मांग का संकेत देते हैं।
- मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए): भारत कई देशों के साथ एफटीए पर बातचीत कर रहा है, जिससे बाजार पहुंच का विस्तार हो सकता है। प्रमुख चिंताएँ:
- नए एफटीए नीतिगत स्थान को प्रतिबंधित कर सकते हैं: सतत विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आईपीआर खंड घरेलू नियामक स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं।
- डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन: भारत को खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग और न्यायसंगत मत्स्य पालन वार्ता जैसे मुद्दों पर जोर देने की जरूरत है।
- अमेरिका और यूरोपीय संघ का व्यापार दबाव: भारतीय निर्यात पर प्रतिकारी टैरिफ और कार्बन सीमा समायोजन की संभावना। सिफारिशें.
- श्रम-गहन क्षेत्रों पर ध्यान दें: कम लागत वाले देशों के खिलाफ प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए रणनीति विकसित करें।
- सेवाओं के निर्यात में विविधता लाएं: पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे गैर-आईटी क्षेत्रों का अन्वेषण करें।
- सेवाओं के लिए डेटा कैप्चर में सुधार: प्रभावी नीति निर्माण के लिए सटीक डेटा महत्वपूर्ण है।
- एफटीए भागीदारों से वास्तविक बाजार पहुंच प्राप्त करें: बातचीत को केवल समझौतों से परे व्यावहारिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- निर्यात के लिए स्थानीय मुद्रा विनिमय विकसित करें: लेनदेन लागत कम करें और रुपये के व्यापार को बढ़ावा दें। • ई-कॉमर्स प्रक्रियाओं को सरल बनाएं: भारतीय ई-कॉमर्स निर्यात की वृद्धि को सुविधाजनक बनाएं।

समग्र दृष्टिकोण:

चुनौतियों के बावजूद, भारत के पास आर्थिक विकास के लिए व्यापार का लाभ उठाने के महत्वपूर्ण अवसर हैं। रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, निर्यात में विविधता लाना और वैश्विक व्यापार परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

प्रीलिम्स ब्लास्टर

सेवा निर्यात में वृद्धि के कारण दुसरी तिमाही में CAD घटकर सकल घरेल उत्पाद का 1% रह गया

परिभाषाः' चालू खाता घाटा एक देश के व्यापार असंतुलन का प्रतीक है जहां आयात का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं में निर्यात के मूल्य से अधिक है।

ा **चालू खाते के घटकःं**

*समावेशः** पूंजी खाते के साथ-साथ भुगतान संतुलन (बीओपी) में योगदान करने वाली शुद्ध आय (जैसे ब्याज, लाभांश) और हस्तांतरण (जैसे विदेशी सहायता) को शामिल करें।

🟋 चालू खाते के घाटे को संबोधित करना:

. रेरणनीतियाँ:** देश निर्यात मुल्यों को बढ़ावा देकर, आयात प्रतिबंध (टैरिफ, कोटा) लगाकर, या वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाने वाली नीतियों पर जोर देकर घाटे को कम कर सकते हैं।

मौद्रिक नीति भूमिका: मौद्रिक नीति के माध्यम से घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात लागत को कम कर सकता है, संभावित रूप से घाटे में कमी लाने में सहायता कर सकता है।

- **खर्च बनाम साधनः** घाटा अत्यधिक खर्च का संकेत दे सकता है; हालाँकि, यह स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है।

- **ऋण प्रबंधन:** ऋण की ब्याज दर से अधिक रिटर्न वाले निवेश के लिए बाहरी ऋण का उपयोग घाटे के बावजूद किसी देश को वित्तीय स्थिति में बनाए

- **सॉल्वेंसी संबंधी विचार:** यदि भविष्य की राजस्व धाराएं मौजुदा ऋण स्तरों को कवर नहीं करेंगी, तो लगातार चालू खाते के घाटे के कारण दिवालियापन एक जोखिम बन जाता है।

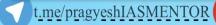
> भारत, रूस ने कुडनकुलम में अधिक परमाणु ऊर्जा इकाइयां बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

- 📜 **परमाणु ऊर्जा समझौते:**
- रूसी तकनीकी सहायता से भारत के सबसे बड़े कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में भविष्य में बिजली पैदा करने वाली इकाइयों के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- पहली इकाई फरवरी 2016 से 1,000 मेगावाट पर काम कर रही है, 2027 तक पुरी क्षमता की योजना है।
- 🔽 कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित
- 🚧 निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ, लेकिन स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण कई देरी का सामना करना पडा।
- 🦞 KKNPP को छह VVER-1000 रिएक्टरों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका निर्माण रूसी राज्य कंपनी एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट और भारत के न्यक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के साथ साझेदारी में किया गया है।
- 🗲 एक बार पूरा होने पर, यह 6,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की स्थापित क्षमता का दावा करेगा।











वीवीईआर (डब्ल्यूडब्ल्यूईआर) दबावयुक्त जल रिएक्टर डिजाइनों की एक श्रृंखला है जिसकी शुरुआत सोवियत संघ में की गई थी और वर्तमान में ओकेबी गिड्रोप्रेस के तहत रूस में विकसित की गई है।

룾 सेवली मोइसेविच फीनबर्ग ने इस रिएक्टर की अवधारणा का प्रस्ताव रखा।

💽 वीवीईआर डिज़ाइनों में पीढ़ी । से लेकर आधुनिक पीढ़ी III+ डिज़ाइन तक निरंतर अद्यतन और संवर्द्धन हुआ है।

🔌 ये रिएक्टर 70 से 1300 मेगावाट तक बिजली उत्पादन प्रदर्शित करते हैं, चल रहे विकास लक्ष्यीकरण डिजाइन 1700 मेगावाट तक पहुंचने में सक्षम हैं।

स्वीडन की नाटो सदस्यता के प्रयास को तुर्की ने समर्थन दिया

जुर्की संसद के विदेशी मामलों के आयोग ने स्वीडन की नाटो सदस्यता बोली का समर्थन किया, जो स्टॉकहोम से अंकारा की सुरक्षा मांगों के कारण एक साल से अधिक की देरी के बाद सैन्य गठबंधन के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

🕥 नाटो में 31 सदस्य देश शामिल हैं - 29 यूरोपीय और दो उत्तरी अमेरिकी, शुरुआत में एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के रूप में स्थापित।

m नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, सैन्य मुख्यालय मॉन्स, बेल्जियम के पास है, और इसने पूर्वी यूरोप में अपनी तैनाती को काफी मजबूत किया है।

🥊 नाटो के पास लगभग 3.5 मिलियन कर्मियों की संयुक्त सैन्य शक्ति है, जो वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग 55% है।

क्म नाटो ने अपनी स्थापना के बाद से नौ बार विस्तार किया है, हाल ही में अप्रैल 2023 में फिनलैंड को 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, स्वीडन के 32वें सदस्य के रूप में शामिल होने की उम्मीद है।



भारत के पास कृत्रिम बारिश की तकनीक है, चरम स्थिति में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा: रिजिजू

कृत्रिम बारिश, या क्लाउड सीडिंग, बारिश या बर्फ के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए हवा में पदार्थों को फैलाकर वर्षा को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है।

इस तकनीक में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, या सूखी बर्फ जैसी सामग्रियों के साथ बादलों को बोना शामिल है, जो चारों ओर पानी की बंदों के निर्माण के लिए नाभिक के रूप में काम करते हैं। ्रि क्लाउड सीडिंग से बड़ी बूंदों का विकास हो सकता है और संभावित रूप से बादलों के भीतर वर्षा को उत्तेजित किया जा सकता है जो अन्यथा बारिश या बर्फ पैदा नहीं कर सकता है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में, देश की अत्यधिक गर्म जलवायु के कारण पानी की कमी से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग रणनीतिक दृष्टिकोण के रूप में किया जाता है।

यूएई क्लाउड सीडिंग तकनीक को अपनाने के लिए फारस की खाड़ी क्षेत्र में अग्रणी है, पूर्वानुमान के अनुसार यह शुष्क वायुमंडलीय परिस्थितियों में लगभग 30-35% और अधिक आर्द्र वातावरण में 10-15% तक वर्षा बढ़ा सकता है।

आईएनएस इम्फाल नौसेना में शामिल: इसकी विशेषताएं, युद्ध क्षमताएं

प्रोजेक्ट 15बी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक के उन्नत संस्करण पेश करता है, जिसमें आईएनएस इम्फाल श्रृंखला में तीसरा जहाज है।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएसएल) द्वारा निर्मित, सभी जहाजों के नाम प्रमुख शहरों- विशाखापत्तनम, मोर्मुगाओ, इंफाल और सूरत के नाम पर रखे गए हैं।

7 आईएनएस इंफाल की आधारशिला 17 मई, 2017 को रखी गई, 20 अप्रैल, 2019 को पानी में लॉन्च किया गया और 26 दिसंबर, 2023 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा।

आईएनएस इम्फाल की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17.4 मीटर और विस्थापन 7,400 टन है, अधिकतम गति 30 समुद्री मील और सीमा 4000 समुद्री मील है।

अायुध में ब्रह्मोस और बराक -8 मिसाइलें, मुख्य बंदूक, क्लोज-पॉइंट एंगेजमेंट बंदूकें, टारपीडो लांचर और पनडुब्बी रोधी रॉकेट लांचर शामिल हैं, और यह दो बह-भूमिका हेलीकाप्टरों को संचालित करने में सक्षम है।

उच्च गति, गतिशीलता और लंबे समय तक सहनशक्ति के लिए डिज़ाइन किया गया, आईएनएस इंफाल उन्नत स्टील्थ सुविधाओं को शामिल करते हुए, सतह, वायु और उप-सतह डोमेन में कम दूरी के हमलावरों से बेड़े और वाहक युद्ध समहों की रक्षा करता है।

🙀 आईएनएस इंफाल जहाज के साथ एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध जोड़ते हुए इंफाल शहर को श्रद्धांजलि देता है।

स्टेल्थ तकनीक का लक्ष्य निष्क्रिय और सक्रिय जवाबी उपायों का उपयोग करके सैन्य संपत्तियों को रडार, इन्फ्रारेड, सोनार और अन्य पता लगाने के तरीकों से कम पता लगाने योग्य बनाना है। इसकी शुरुआत 1958 में अमेरिका में हुई, जिसमें विमान को आकार देने और विकिरण-अवशोषित सामग्री विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर बी-2 स्पिरिट "स्टील्थ बॉम्बर" जैसे विमानों में किया जाता है और यह सैन्य संपत्तियों के डिजाइन और संचालन को प्रभावित करता है, जिससे युद्ध में उनकी उत्तरजीविता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। सतत विकास लगातार सैन्य संपत्तियों की क्षमताओं को आकार देता है।

डील मूल्य सीमा (डीवीटी)

सीसीआई को विलय और अधिग्रहण को अधिसूचित करने, ऐसे सौदों की जांच और विनियमन करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम में डील वैल्यू थ्रेशोल्ड (डीवीटी) की अवधारणा पेश की गई थी।

ा यिंद कोई व्यावसायिक सौदा "सौदा मूल्य सीमा" से अधिक है, तो इसमें शामिल पक्षों को बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नियामक अधिकारियों को सचित करना होगा।